

प्रदेश सरकार ने प्राइमरी के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किये गये थे और शिक्षक संगठनों की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर दो महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकलने तक यह रोक जारी रहेगी। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज शिक्षक संगठनों के साथ बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक का निर्णय लिया गया। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में यह कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी।

राजधानी लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे बसे पंतनगर खुर्रमनगर रहीमनगर और अबरारनगर इलाके के लोगों को अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही से फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि इन क्षेत्रों में बने निजी भवनों को गिराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस क्षेत्र के नागरिकों का आश्वस्त करती है कि उनके मकान नहीं गिराये जायेंगे और अगर रिवरबेड में कोई निजी भूमि में बना मकान आता है, जिसका प्रमाण मकान मालिक देता है तो उसे नियमानुसार मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निजी मकानों पर निशानदेही करने वाले लोगों की जवाबदेही तय की जायेगी और फलड जोन का चिन्हिकरण करने का निर्देश नियमानुसार है लेकिन इस क्षेत्र को खाली कराने की न तो वर्तमान में आवश्यकता है न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। हाल ही में कुकरैल रिवर फ्रंट बनाने के लिये अकबरनगर में अतिक्रमण हटाये जाने के बाद सिंचाई विभाग की टीम ने इन इलाकों में सर्वे कर के मकानों पर लाल निशान लगाये थे। इन निशानों के हटाने के भी निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री से आज इन इलाकों के निवासियों ने मुलाकात की।

प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सत्रह जिलों की चौदह लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है इसके साथ ही लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ के पानी में डूबी हुई है तराई के जिलों के अलावा पूर्वांचल, अवध और रूहेल खण्ड के इलाके भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं हरदोई और शाहजहांपुर जिलों में स्थानीय नदियां उफान पर हैं और शहरी क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंद्रह कंपनी एनडीआरएफ, सोलह कंपनी एसडीआरएफ और बत्तीस कंपनी पीएसी फ्लड बटालियन तैनात की गयी है। पीलीभीत, बलरामपुर, हरदोई जिलों से हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बलरामपुर में राप्ती नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है। वहीं कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है।

वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर गंगा नदी में छोटी नावों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है तेज बहाव के चलते नाविकों को गंगा आरती के दौरान अपनी नाव दशाश्वमेध घाट पर न लगाने की हिदायत दी गयी है। बड़ी नावों को सिर्फ पचास फिसदी यात्री बैठाकर चलने की अनुमति है और शाम को गंगा आरती खत्म होने के बाद कोई भी नाव गंगा नदी में नहीं चलाई जाएगी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दो घाटों का संपर्क टूट गया है।

मिर्जापुर में केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज विन्ध्यवासिनी देवी तीर्थ स्थल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय तीर्थ स्थलों की पर्यटन विकास की छह योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्नीस करोड़ से अधिक की इन परियोजनाओं की आर्ट गैलरी, आरती मंच तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

प्रदेश में बीस जुलाई को साढ़े छत्तीस करोड़ पौधों का रोपण करके रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस बार के अभियान में सहजन के पचपन लाख पौधे भी रोपित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि हर आंगनबाडी केन्द्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के आकांक्षी जिलों के निवासियों को सहजन के पौधे बांटे जाए।

प्रदेश में मोहर्रम का त्यौहार कल मनाया जायेगा। इस सिलसिले में सभी जिलों में प्रशासन सतर्क है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिये हैं कि मोहर्रम के दौरान कोई परम्परा विरुद्ध कार्य न हों और किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जायेगी। गोरखपुर, अम्बेडकरनगर सहित कई जिलों के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने मोहर्रम का जूलूस निकालने के रूट तय कर दिये हैं तथा ड्रोन कैमरों के जरिये पूरे रूट की निगरानी की जायेगी। गोरखपुर में भी कई जगह पर रूट डायवर्जन किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफी कराने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगायी गयी है।
